



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]
No. 150]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 1993/चैत्र 30, 1915
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 1993/CHAITRA 30, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(न्याय विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 381(अ) :—केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश सेवा शर्तें अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 23 व 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिये निम्न-लिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1993 है।
- (2) ये 25 सितम्बर, 1992 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम 1959 के नियम 4 के स्पष्टीकरण में "परन्तु इसमें 360 कि.ली. जल तथा 1200 यूनिट पावर प्रतिमाह से अधिक प्रयोग किये गये जल व विद्युत् के प्रभार शामिल नहीं हैं" शब्दों व अंकों के स्थान पर "परन्तु 4320 कि.लि. जल तथा 17000 यूनिट पावर प्रति वर्ष से अधिक प्रयोग किये गये जल व विद्युत् के प्रभार शामिल नहीं हैं" शब्द व आंकड़े प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

कथित संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से इसलिये लागू किया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासों पर प्रयोग किये गये निःशुल्क जल व विद्युत् के संबंध में दिनांक 25-9-92 से यूनिटों के रूप में निर्धारित किया गया है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1958 (1958 का 41) की धारा 23 की उपधारा 4 के परन्तुओं के अनुसार इस

अधिसूचना के द्वारा प्रस्तावित समय उसी तारीख अर्थात् 25-9-92 से प्रवान करने के लिये लिया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलजी प्रभाव देने से किसी के हित पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

[फा.सं. एल.-11025/26/91-न्याय]

एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

वाद टिप्पणी :—दिनांक 4-8-1958 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 935—भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड (1) पृष्ठ 1161 (मूद्र मंत्रालय संख्या 15/8/58-न्यायिक 1) के तहत प्रकाशित तथा तत्पश्चात् निम्न के द्वारा संशोधित प्रमुख नियम :—

1. सा.का.नि. संख्या 1366, दिनांक 18-12-1974
2. सा.का.नि. संख्या 634, दिनांक 22-4-1976
3. सा.का.नि. संख्या 854, दिनांक 1-8-1980
4. सा.का.नि. संख्या 1176(ई), दिनांक 4-11-1986
5. सा.का.नि. संख्या 680(ई), दिनांक 12-11-1991
6. सा.का.नि. संख्या 559(ई), दिनांक 27-5-1992
7. सा.का.नि. संख्या 779(ई), दिनांक 25-9-1992

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1993

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by sections 23 and 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government

hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 25th day of September, 1992.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 4, in the Explanation, for the words and figures "but excludes the charges on account of water and electricity consumed in excess of 360 kilo litres of water and 1,200 units of power per month", the words and figures "but excludes the charges on account of water and electricity consumed in excess of 4,320 kilo litres of water and 17,000 units of power per annum" shall be substituted.

Explanatory Memorandum

The said amendment is being made retrospectively for the reason that the ceiling in respect of free electricity and water consumed at the official residence of the Judges of the Supreme Court had been prescribed in terms of units with effect from the 25th September, 1992. This decision has been taken in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 23 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958) to extend the benefits proposed by this notification from the same date, i.e., 25-9-1992. It is certified that by giving retrospective effect nobody's interest is likely to be adversely affected.

[File No. L-11025/26/91-Jus.]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

Foot Note : Principal rules published vide Notification No. GSR 939 dated 4-8-1959—Gazette of India Part II—Section 3—Sub-section (i) page 1161 (Ministry of Home Affairs No. 15/6/58-Judl. I).

1. GSR No. 1366, dt. 18-12-1974.
2. GSR No. 634, dated 22-4-1976.
3. GSR No. 854, dt. 1-8-1980.
4. GSR No. 1176 (E), dt. 4-11-1986.
5. GSR No. 680(E), dt. 12-11-1991.
6. GSR No. 559(E), dt. 27-5-1992.
7. GSR No. 779(E), dt. 25-9-1992.